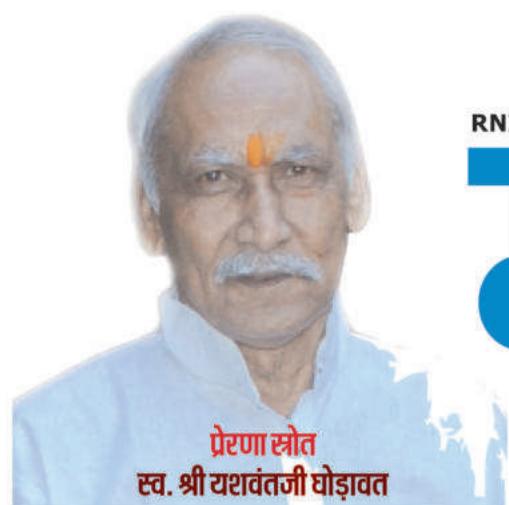




अन्याय
और
अत्याचार
करने वाला,
उन्होंने दोषी नहीं माना जा
सकता, जिनमें कि उसे
सहन करने वाला।
बाल ग्रंथाधार तिलक



माही की गूज

बेबाकी के साथ.. सच

Www.mahikigunj.in, Email-mahikigunj@gmail.com

वर्ष-05, अंक - 19

(साप्ताहिक)

खवासा, गुरुवार 09 फरवरी 2023

पृष्ठ-8, मूल्य -5 रुपए

अगर विकास किया है तो विकास याता की क्या जल्दाता... ?

**जनता के पैसों पर
भाजपा का प्रचार...**

माही की गूज, संजय भटेवारा

झाबुआ कहते हैं कि फूलों की खुशबू को कोई रोक नहीं सकता है, फुल है तो वो महकता है। कछुझी प्रकार भाजपा सरकार ने वास्तव में अगर विकास किया है तो उसे विकास याता की क्या आवश्यकता है...?

भाजपा सरकार को मध्यप्रदेश में 20 वर्ष होने को आए हैं (बीच में 15 माह छोड़कर) उसके बावजूद सरकार को सरकारी खर्च पर विकास याता निकलना कही नहीं रहा दर्शाता है कि, सरकारी योजना का लाभ योजनी स्तर पर नहीं मिल पाया है। भ्रष्टाचार मुक्त शासन का दावा करने सरकार पर 1 वर्ष के बजट के बाबर का कर्ज हो चुका है। एसे में मध्यप्रदेश सरकार पर 1 वर्ष के बजट के बाबर का कर्ज हो चुका है। और इस समय मध्य प्रदेश सरकार पर 3 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्ज हो चुका है। सरकार का एक साल का बजट भी लगभग 3 लाख करोड़ रुपए का रहता है। ऐसे में मध्यप्रदेश सरकार पर 1 वर्ष के बजट के बाबर का कर्ज हो चुका है। इसके सरकार को लोकतान्त्रिक विकास याता पर नहीं रहा है और इसे भ्रष्टाचार पर पर्दा डालकर नया सफना दिखाने वाली योजना है, यह आम जनता का ही नहीं बल्कि चुने हुए जनप्रतिनिधियों का भी करना है।

मध्य प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव हुए करीब 8 माह बीते चुके हैं पर नए जनप्रतिनिधियों के हाथ में आज तक पैसा नहीं आया है वे बढ़े-बढ़े बाद करके स्वयं के खर्च पर चुनाव जीत चुके हैं लेकिन अब के बाद पूरे नहीं कर पा रहे हैं। कुछ जनप्रतिनिधियों ने अनौपचारिक चर्चा में कहा है कि, लगभग 8

माह बीते चुके हैं आने वाले समय में विधानसभा और 2024 में लोकसभा चुनाव होने से अधिकांश समय में आचार सहित लागी रही ऐसे में 2024 लोकसभा चुनाव तक उनका आधा कार्यकाल बीत जाएगा ऐसे में जनता से किए गए वादे किस प्रकार पूर्ण करेंगे।

उदार लो स्थीर पीयो

एक खबर के अनुसार मध्य प्रदेश सरकार ने इस वित्तीय वर्ष में 17 हजार करोड़ रुपए का कर्ज ले लिया है और इस समय मध्य प्रदेश सरकार पर 3 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्ज हो चुका है। सरकार का एक साल का बजट भी लगभग 3 लाख करोड़ रुपए का रहता है। ऐसे में मध्यप्रदेश सरकार पर 1 वर्ष के बजट के बाबर का कर्ज हो चुका है। और इस समय मध्य प्रदेश सरकार पर पर्दा डालकर नया सफना दिखाने वाली योजना है, यह आम जनता का ही नहीं बल्कि चुने हुए जनप्रतिनिधियों का भी करना है।

मध्य प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव हुए करीब 8 माह बीते चुके हैं पर नए जनप्रतिनिधियों के हाथ में आज तक पैसा नहीं आया है वे बढ़े-बढ़े बाद करके स्वयं के खर्च पर चुनाव जीत चुके हैं लेकिन अब के बाद पूरे नहीं कर पा रहे हैं। कुछ जनप्रतिनिधियों ने अनौपचारिक चर्चा में कहा है कि, लगभग 8

भ्रष्टाचार बना शिष्टाचार

वर्तमान में भ्रष्टाचार, शिष्टाचार बन चुका है और यह भ्रष्टाचार आम जनता के साथ ही नहीं कर पा रहे हैं। कुछ जनप्रतिनिधियों के साथ भी ही हो रहा है। कुछ चुने हुए



कहानी स्वयं बतला रहे हैं।

पानी के टैंकरों की स्थिति

प्रतिवर्ष जल संकट की समस्या से निपटने के लिए सांसद, विधायक द्वारा ग्राम पंचायतों के टैंकर दिए जाते हैं लेकिन वे टैंकर किस प्रकार कर सकते हैं यह जग जाहिर है अगर वर्तमान में देखा जाए तो गिने-चुने टैंकर ही चाल बालत में मिलेंगे लेकिन रिकॉर्ड में सैकड़ों टैंकर होंगे।

शिक्षा और स्वास्थ्य

सरकार की सबसे प्रमुख जिम्मेदारी आम जनता को निशुल्क शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराना लेकिन आज मामूली बुखार का इलाज कराना ही तो भी आम नागरिक को निजी अस्पतालों में जान पड़ता है। व्यावधानीक सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर ही नहीं है यहां हाल शासकीय विधालयों का भी है यहां शिक्षक ही नहीं है।

उद्धारी पर मनरेगा

मजदूरों को 100 दिनों की मजदूरी सुनिश्चित करने हुए राष्ट्रीय रोजगार गारंटी (मनरेगा) लागू है लेकिन इस योजना में 1-1, 2-2 साल बीत जाने के बाद भी सरकारी पैसे नहीं मिलने के कारण मजदूरों की मजदूरी नहीं मिलती है। वही

राहुल गांधी की मानसिक आयु पर सीएम शिवराज को संदेह...?

भोपाल।



लोकसभा में दिए राहुल गांधी के भाषण पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उनकी मानसिक उम्र को लेकर तंज करा। सीएम शिवराज सिंह ने कहा है कि उनकी मानसिक आयु अपने भाषण के निशाने पर आ गए थे।

दीर्घ तीसे से बृद्धि पर सवाल पूछा था। जिसके बाद बुधवार को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उनकी मानसिक उम्र को लेकर कठाक किया है। राहुल गांधी ने अपने भाषण के दौरान पीएम मोदी और गौतम अडानी के बीच रिश्तों को लेकर भी सवाल खड़े किए।

सदन में लेकर आए फोटो

अपने भाषण के दौरान राहुल गांधी सदन में फोटो लेकर भी आए थे। उस फोटो में हवाई जहाज के अंदर पीएम मोदी के साथ अधिनियम यूपीए पर निशाना कर रहे हैं। राहुल गांधी की इस फोटो के जबाब में भाषणा के साथ बोलते हैं। फोटो लेकर वर्षों नहीं आए...?

दीर्घ तीसे से बृद्धि पर सवाल पूछा था। जिसके बाद बुधवार को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उनकी मानसिक उम्र को लेकर कठाक किया है। राहुल गांधी ने अपने भाषण के निशाने पर आ गए थे।

भाजपा के निशानों पर उन्होंने आए...?

दीर्घ तीसे से बृद्धि पर सवाल पूछा था। जिसके बाद बुधवार को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उनकी मानसिक उम्र को लेकर कठाक किया है। राहुल गांधी ने अपने भाषण के निशानों पर आ गए थे।

दीर्घ तीसे से बृद्धि पर सवाल पूछा था। जिसके बाद बुधवार को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उनकी मानसिक उम्र को लेकर कठाक किया है। राहुल गांधी ने अपने भाषण के निशानों पर आ गए थे।

दीर्घ तीसे से बृद्धि पर सवाल पूछा था। जिसके बाद बुधवार को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उनकी मानसिक उम्र को लेकर कठाक किया है। राहुल गांधी ने अपने भाषण के निशानों पर आ गए थे।

दीर्घ तीसे से बृद्धि पर सवाल पूछा था। जिसके बाद बुधवार को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उनकी मानसिक उम्र को लेकर कठाक किया है। राहुल गांधी ने अपने भाषण के निशानों पर आ गए थे।

दीर्घ तीसे से बृद्धि पर सवाल पूछा था। जिसके बाद बुधवार को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उनकी मानसिक उम्र को लेकर कठाक किया है। राहुल गांधी ने अपने भाषण के निशानों पर आ गए थे।

दीर्घ तीसे से बृद्धि पर सवाल पूछा था। जिसके बाद बुधवार को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उनकी मानसिक उम्र को लेकर कठाक किया है। राहुल गांधी ने अपने भाषण के निशानों पर आ गए थे।

दीर्घ तीसे से बृद्धि पर सवाल पूछा था। जिसके बाद बुधवार को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उनकी मानसिक उम्र को लेकर कठाक किया है। राहुल गांधी ने अपने भाषण के निशानों पर आ गए थे।

दीर्घ तीसे से बृद्धि पर सवाल पूछा था। जिसके बाद बुधवार को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उनकी मानसिक उम्र को लेकर कठाक किया है। राहुल गांधी ने अपने भाषण के निशानों पर आ गए थे।

दीर्घ तीसे से बृद्धि पर सवाल पूछा था। जिसके बाद बुधवार को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उनकी मानसिक उम्र को लेकर कठाक किया है। राहुल गांधी ने अपने भाषण के निशानों पर आ गए थे।

दीर्घ तीसे से बृद्धि पर सवाल पूछा था। जिसके बाद बुधवार को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उनकी मानसिक उम्र को लेकर कठाक किया है। राहुल गांधी ने अपने भाषण के निशानों पर आ गए थे।

दीर्घ तीसे से बृद्धि पर सवाल पूछा था

आखिर कौन है मालिक इस हवा महल का, अवैध हटाने वाले ही अवैध बनाएंगे तो क्या होगा...?

माही की गूँज, पेटलावद। साकेत गेलोत

नगर के मुख्य मार्ग से लगे श्रद्धांजलि चौराहे पर बना एक भवन चर्चा का विषय बना हुआ है। पेटलावद भवन का मालिक कौन है इसका अता पता नहीं है। इसलिए लोग इसे हवा महल बोल रहे हैं। यह रोपण से और चर्चाओं में इसे पुलिस चौकी बताया जा रहा है लेकिन कोई भी विभाग इसकी प्रमाणित पुष्टि करने को तैयार नहीं है। वही स्थानीय पुलिस अधिकारी भी इस भवन पर सवाल करने वालों को खुल कर कोई जवाब नहीं दे पारे हैं। क्वैसे तो पुलिस के अनुमति से सभव होता है लेकिन यह अवैध रूप से बना ये भवन आँफ द रिकॉर्ड कठी दर्ज नहीं है।

अतिक्रमण में बना है पूरा

भवन, निर्माण होने की शुरुआत से उठ रहे सवाल

वैसे तो नगर परिषद प्रशासन ऐसे अवैध रूप से होने वाले निर्माण पर तुरंत एकशन लेता है। सड़क के किनारे बनी दुकानों के आगे अतिक्रमण में लगे ढालिये तक तोड़



देती है लेकिन निर्माण की शुरुआत से खड़े हो रहे सवालों के बीच स्थानीय प्रशासन और नगर परिषद अर्ख बंद रख बिल्कुल की भाँति दूध पी रहे हैं। ऐसा नहीं की उक्त भूमि और निर्माण को लेकर दावे आपत्ति दर्ज नहीं कराए गए हो, लेकिन वर्दी की धोस के आगे सभी नमस्कर दिखे। हाँ, यहा रोड की एजेंसी एमपीआरडीसी ने जरूर इस निर्माण

पर सवाल उठा कर नोटिस जारी किए थे लेकिन घृणा फिर कर बात स्थानीय प्रशासन पर ही आ गई जो इस अवैध निर्माण को लेकर अपनी मौन स्वीकृति पहले ही दे चुके थे।

वसुली या जन सहयोग

भवन निर्माण में लगने वाली सामग्री भी

जन सहयोग के नाम पर वसुली कर लगाई गई है। ईट, सीमेंट, सिरिया सहित समस्त लगने वाली सामग्री दान दाता के माध्यम से आई है लेकिन दान स्वेच्छिक ही होकर जबरजस्ती करवाया गया हुआ है। दान देने वाले दबी जुबान से बोल रहे हैं। पुलिस वालों से कौन पांगा ले, कुछ ईंट वाले सामग्री ए रोप और पंगु प्रशासन की निशानी के रूप में पहचाना जाएगा।

देखा जाए तो ये भवन किसी पुलिस चौकी के नाम से कम और उलिस दालागिरी और प्रशासन के नियम विरुद्ध काम को स्वीकृति के लिए पहचाना जाएगा। नगर की कुछ संस्थाओं को इस निर्माण के लिए ढाल बनाया गया है जो पुलिस को इस भवन निर्माण के सहयोग का हवाला देकर या मधुर हुए सबधों का लाभ उठा कर इसकी कीमत वसूल करें।

दोहरा मापदंड ठीक नहीं

जिस प्रकार से पूर्व में नगर में आई अतिक्रमण मुहिम में गयी थी के घर तोड़े गए और आये दिन नगर परिषद अतिक्रमण के नाम पर स्थानीय दुकानदारों को नुकसान पहुँचाया जाता है जही अवैध रूप से हुवे इस निर्माण की लगातार शिकायतों के बाद भी प्रशासन दोहरा मापदंड अपनाते हुवे कोई कार्यवाही नहीं की जो समाज के लिए इस प्रकार का दोहरा मापदंड ठीक नहीं है। येर जो भी हो नगर के मुख्य चौराहे पर इस भवन में चौकी बने या कुछ और ये भवन वर्दी के रोप और पंगु प्रशासन की निशानी के रूप में पहचाना जाएगा।

इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप पर योजना का लाभ उठ रहे वाहन चालक

माही की गूँज, सारंगी।

संजय उपाध्याय

इंडियन ऑयल कंपनी द्वारा ग्राहकों की सुविधा के लिए एक भवन जाएगा। नगर की कुछ संस्थाओं को इस निर्माण के लिए ढाल बनाया गया है जो पुलिस को इस भवन निर्माण के सहयोग का हवाला देकर या मधुर हुए सबधों का लाभ उठा कर इसकी कीमत वसूल करें।



दोहरा मापदंड ठीक नहीं

संचालक संदीप पाटीदार ने बताया कि, यह योजना 28 फरवरी तक रही इसमें ग्राहकों को अपने 10 अंकों का अनाना मोबाइल नंबर देकर ओटीपी आने पर ग्राहक का मोबाइल नंबर इंडियन ऑयल कंपनी में रेगिस्टर होगा। ओटीपी आने के बाद में रेगिस्टर होने के बाद एप्प पेट्रोल पंप 50 रुपये की ईपेट्रोल डाल रहे हैं।

रेगिस्टर होने के बाद एप्प पेट्रोल भवताव है तो उसको कंपनी की तरफ से एक कार्ड बनाया जाएगा और जब 100 पॉइंट होने पर ग्राहक को इंडियन ऑयल कंपनी द्वारा योजना के तहत उपहार दिया जाएगा।

पेट्रोल पंप संचालक ने सभी ग्राहकों से अपील की है इस स्कीम के तहत पेट्रोल भवताव इंडियन ऑयल कंपनी की तरफ से उत्तम चालक नाम पाएं।

पेट्रोल पंप पर योजना का लाभ उठा कर इस स्कीम पर लाभ लेना।

पेट्रोल पंप संचालक ने सभी ग्राहकों की तरफ से उत्तम चालक नाम पाएं।

पेट्रोल पंप पर योजना का लाभ उठा कर इस स्कीम पर लाभ लेना।

पेट्रोल पंप संचालक ने सभी ग्राहकों की तरफ से उत्तम चालक नाम पाएं।

पेट्रोल पंप पर योजना का लाभ उठा कर इस स्कीम पर लाभ लेना।

पेट्रोल पंप संचालक ने सभी ग्राहकों की तरफ से उत्तम चालक नाम पाएं।

पेट्रोल पंप संचालक ने सभी ग्राहकों की तरफ से उत्तम चालक नाम पाएं।

पेट्रोल पंप संचालक ने सभी ग्राहकों की तरफ से उत्तम चालक नाम पाएं।

पेट्रोल पंप संचालक ने सभी ग्राहकों की तरफ से उत्तम चालक नाम पाएं।

पेट्रोल पंप संचालक ने सभी ग्राहकों की तरफ से उत्तम चालक नाम पाएं।

पेट्रोल पंप संचालक ने सभी ग्राहकों की तरफ से उत्तम चालक नाम पाएं।

पेट्रोल पंप संचालक ने सभी ग्राहकों की तरफ से उत्तम चालक नाम पाएं।

पेट्रोल पंप संचालक ने सभी ग्राहकों की तरफ से उत्तम चालक नाम पाएं।

पेट्रोल पंप संचालक ने सभी ग्राहकों की तरफ से उत्तम चालक नाम पाएं।

पेट्रोल पंप संचालक ने सभी ग्राहकों की तरफ से उत्तम चालक नाम पाएं।

पेट्रोल पंप संचालक ने सभी ग्राहकों की तरफ से उत्तम चालक नाम पाएं।

पेट्रोल पंप संचालक ने सभी ग्राहकों की तरफ से उत्तम चालक नाम पाएं।

पेट्रोल पंप संचालक ने सभी ग्राहकों की तरफ से उत्तम चालक नाम पाएं।

पेट्रोल पंप संचालक ने सभी ग्राहकों की तरफ से उत्तम चालक नाम पाएं।

पेट्रोल पंप संचालक ने सभी ग्राहकों की तरफ से उत्तम चालक नाम पाएं।

पेट्रोल पंप संचालक ने सभी ग्राहकों की तरफ से उत्तम चालक नाम पाएं।

पेट्रोल पंप संचालक ने सभी ग्राहकों की तरफ से उत्तम चालक नाम पाएं।

पेट्रोल पंप संचालक ने सभी ग्राहकों की तरफ से उत्तम चालक नाम पाएं।

पेट्रोल पंप संचालक ने सभी ग्राहकों की तरफ से उत्तम चालक नाम पाएं।

पेट्रोल पंप संचालक ने सभी ग्राहकों की तरफ से उत्तम चालक नाम पाएं।

पेट्रोल पंप संचालक ने सभी ग्राहकों की तरफ से उत्तम चालक नाम पाएं।

पेट्रोल पंप संचालक ने सभी ग्राहकों की तरफ से उत्तम चालक नाम पाएं।

पेट्रोल पंप संचालक ने सभी ग्राहकों की तरफ से उत्तम चालक नाम पाएं।

पेट्रोल पंप संचालक ने सभी ग्राहकों की तरफ से उत्तम चालक नाम पाएं।

पेट्रोल पंप संचालक ने सभी ग्राहकों की तरफ से उत्तम चालक नाम पाएं।

पेट्रोल पंप संचालक ने सभी ग्राहकों की तरफ से उत्तम चालक नाम पाएं।

पेट्रोल पंप संचालक ने सभी ग्राहकों की तरफ से उत्तम चालक नाम पाएं।

पेट्रोल पंप संचालक ने सभी ग्राहकों की तरफ से उत्तम चालक नाम पाएं।

पेट्रोल पंप संचालक ने सभी ग्राहकों की तरफ से उत्तम चालक नाम पाएं।

पेट्रोल पंप संचालक ने सभी ग्राहकों की तरफ से उत्तम चालक नाम पाएं।

पेट्रोल पंप संचालक ने सभी ग्राहकों की तरफ से उत्तम चालक नाम पाएं।

पेट्रोल पंप संचालक ने सभी ग्राहकों की तरफ से उत्तम चालक नाम पाएं।

पेट्रोल पंप संचालक ने सभी ग्राहकों की तरफ से उत्तम चालक नाम पाएं।

पेट्रोल पंप संचालक ने सभी ग्राहकों की तरफ से उत्तम चालक नाम पाएं।

पेट्रोल पंप संचालक ने सभी ग्राहकों की तरफ से उत्तम चालक नाम पाएं।

पेट्रोल पंप संचालक ने सभी ग्राहकों की तरफ से उत्तम चालक नाम पाएं।

पेट्रोल पंप संचालक ने सभी ग्राहकों की तरफ से उत्तम चालक नाम पाएं।

पेट्रोल पंप संचालक ने सभी ग्राहकों की तरफ से उत्तम चालक नाम पाएं।

पेट्रोल पंप संचालक ने सभी ग्राहकों की तरफ से उत्तम चालक नाम पाएं।

पेट्रोल पंप संचालक ने सभी ग्राहको

संपादकीय

चीनी ऐपों के चक्रव्यूह पर लगा प्रतिबंध

केंद्र सरकार ने चीनी लिंक वाले सैकड़ों मोबाइल फोन ऐप पर प्रतिबंध लगाकर 'देर आए दुरस्त आए' की कहावत को चरितार्थ किया है। जो इस बात का संकेत भी है कि, हमारा निगरानी और नियामक तंत्र मजबूत हुआ है। यह कदम इस बात की आवश्यकता को



दरशाता है कि इस दिशा में आगे भी सजग रहने की जरूरत है। दरअसल 138 सट्टेबाजी को बढ़ावा देने वाले और 94 ऋण देने वाले एप्स पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय इस बाबत मिली शिकायतों के बाद लिया गया। आरोप है कि, इन ऐप के उपयोगकर्ताओं से जबरन वसूली और उनके उत्पीड़न की शिकायत मिल रही थी। जहां एक ओर इन ऐपों के जरिए व्यक्तिगत डेटा में संदेशमारी की जा रही थी, वहीं ऋण वसूली के नाम पर आतंकित भी किया जाता रहा है। ये ऐप नियमक एजेंसियों की जांच के दायरे में थे। दरअसल, ऐसे ऐप्स के जरिए चीनी नागरिकों ने शातिराना अंदाज में अपने लक्ष्यों की पूर्ति के लिए भारतीयों को परिचालन की जिम्मेदारी सौंप रखी थी। इनके भारतीय संचालक पैसे की जरूरत वाले लोगों को छोटे ऋण लेने को उकसाते थे और अप्रत्याशित रूप से व्याज की ऊंची दरें वसूलते थे। इतना ही नहीं, कर्जदारों का मानसिक उत्पीड़न किया जाता था। उनकी प्रतिष्ठा को टेस पहुंचाने के लिए लैंकमेल किया जाता था। इतना ही नहीं छेड़छाड़ करके बनाई गई तस्वीरों को कर्ज लेने वालों के रिश्तेदारों व परिचितों को भेजने की धमकी दी जाती थी। उन्हें भद्दे संदेश भी भेजे जा रहे थे। इन ऐप्स के संचालन से जुड़े भारतीय लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की जानी चाहिए। नि:संदेश, भारत आज इंटरनेट के तमाम खिलाड़ियों और उससे जुड़ी नई तकनीक को बाजार में उतारने वाली संस्थाओं के लिए बड़ा बाजार है। वहीं देश में बढ़ता ३०८लाइन लेन-देन साइबर अपराधों और उससे जुड़े सुरक्षा जोखिमों के प्रति संवेदनशील बनाता है। पिछले कुछ वर्षों में भारत की सुरक्षा, गोपनीयता और डेटा से जुड़ी चिंताओं के चलते चीन के ऐप्स संदेश के घेरे में रहे हैं।

इन्हें संदेह है, चीन की सीमा पर जारी गतिरोध के बीच भारतीय रणनीतिकारों ने भी इस दिशा में कार्रवाई की जरूरत महसूस की होगी। वर्ष 2020 में विवादित चीनी एप टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने के भारतीय प्रयासों को पश्चिमी देशों ने साहसिक मिसाल के तौर पर देखा है। तब भी युवाओं में बहेट लोकप्रिय चीनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उपयोगकर्ताओं के फोन से जानकारी एकत्र करने की बात सामने आई थी। आशंका थी कि, चीनी अधिकारी इस संवेदनशील डेटा का उपयोग भारत के खिलाफ कर सकते हैं। देश में साइबर हमलों में आपत्त्याशित वृद्धि हुई है। वर्ष 2019 में साइबर हमलों की संख्या जहां 3.94 लाख थी, वहीं वर्ष 2021 में इनकी संख्या बढ़कर 14.02 लाख हो गई है। इस दिशा में युद्ध स्तर पर उपाय करने की जरूरत महसूस की जा रही है। आम लोगों के साथ आधुनिक तकनीक के नाम पर किये जा रहे छल को गम्भीरता से लेना चाहिए। आज भारत में जन सुविधाओं के लिये ऐपों के उपयोग में भारी वृद्धि हुई है। लेकिन साथ ही साइबर टगी के मामलों में तेजी आई है। आईटी के माहिर शातिर लोग आम आदमी की जरा सी चूक पर उसका खाता खाली कर देते हैं। अकसर शक की सूई चीनी एप की ओर मुड़ जाती है। ऐसे में केंद्र सरकार की हालिया पहल इस तकनीकी फर्जीवाड़े पर लगाम लगाने की कोशिश के रूप में देखी जा सकती है। सरकार कई चरणों में पहले भी ऐसी कोशिश कर चुकी है। विंडबंडा यह है कि, सुरक्षा एजेंसियों व नियामक संस्थाओं की व्यवस्था को फुलप्लूफ बनाने की कोशिश में शातिर लोग टगी के नये रास्ते तलाश लेते हैं। कई बार इन शातिर ऐप संचालकों की चपेट में आये लोग दुःखी होकर आत्महत्या करने तक को मजबूर हो जाते हैं। ऐसे में कई ऐपों पर प्रतिबंध लगाना सरकार द्वारा लोगों की व्यक्तिगत जानकारी व अन्य डेटा के संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम कहा जा सकता है। आज आम लोगों को ऑनलाइन सेवाओं के उपयोग के लिये प्रशिक्षित करने व जागरूक बनाने की पहल होनी चाहिए।

भाजपा को भारी पड़ेगी महिला नेताओं की नराजगी

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को अगले लोकसभा चुनाव तक अध्यक्ष पद का कार्य विस्तार मिल चुका है। अगले लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए नड्डा ने अपने संगठन को पुनर्गठित और चुस्त-दुरुस्त करना शुरू कर दिया है। लोकसभा चुनाव से पूर्व जम्मू कश्मीर सहित दस प्रदेशों की विधानसभाओं के चुनाव होने हैं। जिनके नतीजों से पता चल जाएगा कि अगले लोकसभा चुनाव में कौन सी पार्टी

केंद्र में सरकार बना सकेगी। चुनावों वाले दस राज्यों से लोकसभा की कुल 121 सीट आती है। ऐसे में ऐसे में जिस पार्टी की भी सरकार इन प्रदेशों में बनेगी स्वाभाविक ही है कि लोकसभा चुनाव में भी उसी पार्टी का अधिक प्रभाव दिखेगा। हालांकि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड़ा खुद अपने गृह प्रदेश हिमाचल प्रदेश में भाजपा की सरकार को नहीं बचा सके और वहां पर कांग्रेस भारी बहुमत के साथ सरकार बनाने में कामयाब हो गई। इससे लगता है कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में नड़ा शायद ही कुछ करिशमा दिखा पाए। पूरा चुनाव प्रधानमंत्री नेंद्र मोदी के इंद-गिर्द ही रहता लग रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेता अभी से आगले लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट चुके हैं। आगले लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए भी ही पार्टी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर किसी नए नेता को लाने की बजाय जेपी नड़ा को ही रखने का फैसला किया है। भाजपा का मानना है कि नड़ा की पूरी टीम का सेटअप बना हुआ है। ऐसे में नए सिरे से संगठन बनाने में काफी

समय निकल जाएगा। प्रभारी ने भी देशरथ में अपने दिए हैं। भाजपा के नेता परमाणुकरण में नजर आने लगे हैं। परमाणुकरण में सरकार बनाने का समय भी बढ़ावा दिया गया है। भाजपा की ही कुछ विधायिकाओं की नाराजगी आने वाले भारी पड़ सकती है।

बुकुरा राज स्थान का नेता राजस्थान में खुद को ने मांग करती आ रही है। वह है कि दिसंबर में होने वालुनाव में पार्टी उन्हें नेता लड़े। मगर भाजपा आलोक के मूढ़ में नहीं लगता है। राजे भाजपा की राजनीति कहने को तो उन्हें पार्टी बनाया गया है। मगर उनकी कोई भूमिका न जान राजस्थान की राजनीति का कद बहुत बड़ा माना जाता है। भाजपा में तो वासुधारा राजनीति दूसरा नेता नहीं है। उन्हें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दूसरी बार कांग्रेस की दावा कर रहे हैं। राज्य के पेशन योजना लागू करना मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खासे लोकप्रिय हो रहे हैं कि उनका अगला बजट भी काम होगा। ऐसे में गहलोत का

एमपी में जनता के आंगन में सरकारी विकास यात्राओं की आमद

मध्यप्रदेश में वर्ष 2023 राजनैतिक हलचल से भरपूर रहने वाला है। चुनावी साल होने से जनता को अपना भगवान बताने वाले राजनैतिक दल जिनमें सत्ताधारी भाजपा और सत्ता पाने की जुगत में लगी कांग्रेस सहित नई नवेली आमआदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी जनता के दरबार में जाकर अपने दल को जनता का सबसे बड़ा हितेशी बताने का प्रयास करेंगे। आमजन भी यह सोच रहा है कि 4 साल अपने छोटे से काम के लिए सरकारी दफतरों के चक्कर काटने होते हैं। उस दौरान अफसस मिलते नहीं, नेता गायब रहते हैं। अब जबकि चुनावी साल है। सत्ताधारी ओर विपक्षी नेताओं द्वारा पूछप्रश्न की जा रही है। मध्यप्रदेश की सत्ता पर भारतीय जनता पार्टी कबिज है। प्रदेश में 15 महीनों की कमलनाथ सरकार के शासनकाल को छोड़ दें तो करीब 20 साल से एमपी में भारतीय जनता पार्टी का शासन रहा है। इन 20 सालों में अधिकांश समय प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर शिवराज सिंह चौहान कबिज रहें हैं। प्रदेश सरकार फरवरी की 5 तारीख से 25 तारीख तक मध्यप्रदेश के 55 जिलों, 16 नगर निगमों, 100 नगरपालिकाओं, 264 नगर पंचायतों, 313 विकासखण्डों की 23 हजार से अधिक ग्राम पंचायतों में विकास यात्रा निकाल रही है। यानी सरकार जनता के आंगन में आमद देकर यह बताने की कोशिश कर रही है कि हम आपके सबसे बड़े हितेशी हैं। हमारी सरकार ने आपका पूरा ध्यान रखा है। प्रदेश में चारों ओर खुशहाली का बातावरण व्याप्त है, जनता को घर बैठे सरकारी सुविधाएं मिल रही हैं। प्रदेश का कृषक खुशहाल है, उसे आसानी से खाद, बीज, यूरिया उपलब्ध हो रहा है। किसान को उसकी फसल का अच्छा दाम मिल रहा है। सरकार की नीतियों से व्यवसायी वर्ग में भी प्रसन्नता व्याप्त है। वह बड़े अच्छे माहौल में अपना व्यवसाय कर रहा है। प्रदेश के उद्योग धंधे फलपूत्र रहें हैं। सरकार की नीतियों से व्यवसायिक वर्ग भी गदगद है। प्रदेश के बेरोजगार भी प्रदेश की शिवराज सरकार से हर्षित हैं। युवा बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने में सरकार ने काफी प्रयास किये हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, राशन, सड़क, पानी, बिजली जैसी बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता से आमनागरिक के जीवन में शिवराज सिंह की वर्तमान सरकार ने बंसत बाहर ला दी है। कुल मिलाकर जनता को सरकार द्वारा प्रायोजित विकास यात्राओं के माध्यम से यह बताने की कोशिश की जाएगी कि शिवराज की सरकार ने बेहतर काम किया है। जनता को आगे भी इस सरकार को मौका देना चाहिए। सरकारी प्रयास से प्रदेश की सम्पूर्ण मरीनीरी आमआदमी के दिमाग में यह बिठाने की पूरी कोशिश करेगी की एमपी की शिवराज सरकार के राज में प्रदेश तरक्की कर रहा है। जनता के आंगन में विकास का यह रथ जनता की तरक्की की असली तस्वीर है। विकास के शोर मचाते इन रथों से सरकारी भोपू प्रदेश को खुशहाल बताने के हर सम्भव जतन करेंगे। इसके विपरीत प्रदेश के प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने 5 फरवरी को ग्वालियर में एक जनसभा को सम्बोधित करते हुए भाजपा सरकार की विकास यात्रा को नौटंकी करार दिया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की कुछ उपलब्धियाँ होती हैं, नहीं सिर्फ सरकार के पैसों का दुरुपयोग किया जा रहा है। विकास होता ही विकास यात्रा निकालने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। कमलनाथ अपने 15 महीने की उपलब्धियाँ गिनाना भी नहीं भूलते। दूसरी ओर उपलब्धियाँ गिनाना भी नहीं भूलते।

नेपाल विवाद में बेमतलब भारतीय एंट्री

नपाल के ताजा राजनातक विवाद में प्रधानमंत्री मोदी की जबरदस्ती एंगी कराई जा रही है। यह सब करने वाले कोई और नहीं, उप-प्रधानमंत्री-सह-गृहमंत्री पद से बेदखल हो चुके रवि लामिखने हैं। लामिखने ने कहा, 'मोदी जी, आपके नाम पर लोग यहां पर लूट मचा रहे हैं, वे भारत और नेपाल के लिए क्या कर रहे हैं? आपके एजेंट के नाम पर जो लोग यहां काम कर रहे हैं, उनके ऊपर भरोसा करना बंद करिए। आप एक सीधी बातचीत के लिए आगे बढ़ें। कृपया उन लोगों को रोकें, जो भारतीय सरकार अपनी जातियां द्वारा

रुख का असला जानकार हान का दावा करते हैं। यदि आप वास्तव में नेपाल और भारत के बीच बेहतर रिश्टें चाहते हैं, तो किसी मध्यस्थिति, पत्रकार, एजेंट या पब्लिशर को तैनात मत करिए।'

27 जनवरी 2023 को रवि चाहियो द्वारा उन्नीसवें अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस पर

दिन स्थित गृहमंत्री की कुर्सी दोबारा से दे दें। जब इसकी सूरत नजर नहीं आ रही थी, तो रासवापा के तीन मंत्रियों ने पद से इस्तीफा दे दिया। इनमें शिंशिर खनाल शिक्षा-विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रकमें से, डेल प्रसाद आयरलंथ्रम, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा मंत्री पद से, चतुरपाल और उत्तरांशुल प्रत्यार्पित पद

2007 से 2017 तक अमेरिकी नागरिक होने का लाभ उठाया। मगर, नागरिकता अधिनियम की धारा 10 कहती है कि कोई भी नेपाली नागरिक जो स्वेच्छा से किसी विदेशी देश की नागरिकता प्राप्त करता है, वह स्वतः ही नेपाल की नागरिकता खो देगा। यदि कोई अपनी विदेशी नागरिकता का त्याग करता है तो नेपाली नागरिकता पुनः प्राप्त करने के लिए उसे आवेदन करना होगा। रवि लामिङ्हाने नेपाल में राजा कहा, और 21 जून को र १६८२ य स्वतंत्र पार्टी (रास्वपा) बनाने की घोषणा कर दी। तब पुरारजन विश्लेषकों का आकलन था कि रालामिङ्हाने की टीम, नेपाल में सबसे सूपड़ा सफ कर देगी। मगर, 2 नवंबर, 2022 के आम चुनाव 'रास्वपा' के कुल 20 नेता सफल पाये। जिनमें सात निर्वाचित और 1

समर्थक राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी के महासचिव रह चुके उद्घव पौडेल के दामाद भी हैं। नेपाल फ़िल्म डेवलपमेंट बोर्ड का चेयरपरसन रह चुकीं निकिता पौडेल से रवि लामिङ्गने ने 17 मई, 2019 को प्रेम विवाह किया था। शादी के समय अदालत में जो नागरिकता पत्र प्रस्तुत करा दी गई उसमें इस विवाह की विवाहितता नहीं दर्शाया गया।

हुआ, वा भा जाच का विषय ह। 5 फरवरी 2023 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में रवि लामिछाने ने बयान दिया कि नेपाल का मीडिया गैर जिम्मेदार है, कुछ मीडिया हाउस और संपादकों के निशाने पर मैं था, इसलिए यह सब हुआ है। रवि लामिछाने का यह बयान तूल पकड़ चुका है। फेडरेशन ऑफ नेपाल जननिट्स (एफएनजे) और नेपाल प्रेस यूनियन ने रवि लामिछाने के बड़बोलपन को मुद्दा बना लिया है। इन संगठनों ने कहा कि यह पत्रकार विवादिरी पर हमला है, नेपाली मीडिया निष्पक्षता के मामले में पूरे दक्षिण एशिया में दूसरे स्थान पर है, ऐसा रिपोर्ट विडाउट बॉर्डर भी मानता है। मान ला गढ़ा 11 जनवरी, 2023 लामिछाने को उपप्रधानमंत्री का पांच और मनन्चाहा मंत्रालय मिला। इस अति महत्वाकांक्षा की बजह लामिछाने आलोचना के केंद्र में रखा गया। जो लोग रवि लामिछाने क्रातिकारी बदलाव वाले नेता वा अवस देखते थे, उनका मोहब्बंग जल्द हो गया।

पत्रकार अपनी प्रसिद्धि के साथ दुश्मन भी पैदा करता है। रवि लामिछाने का नामिकता वाला विवाद नया नहीं है। 2018 में सब पहले प्रेस कॉसिल में शिकायत आई कि लामिछाने बिना वर्क परमिट नेपाल में कार्यरत है, क्योंकि वह अभी भी अमेरिकी नागरिक है। अंततः रो

14 सितंबर 1974 को भक्तपुर में जन्मे रवि लामिछाने ने रत्न राज कैपिंस से हाईस्कूल तक पढ़ाई की, फिर अमेरिका के बाल्टीमोर से मास कॉम की पढ़ाई की। वहां सब-वे में नौकरी भी की। एक अमेरिकी नागरिक ईशा से विवाह किया। बताते हैं कि दोनों से एक बेटी भी हुई थी। ईशा से तलाक लेकर 2014 में रवि लामिछाने अमेरिका से काठमांडौ आये, और टीवी जर्नलिस्ट बन गये। पत्रकार रवि लामिछाने का टीवी शो, 'सीधी कुरा' (सीधी बातचीत) नेपाल में हिट था। उससे पहले एक और टीवी शो होस्ट करते थे, 'बुद्धा वाज बॉन्न इन नेपाल।' रवि लामिछाने ने कल प्रियंग आगेराण भी किये थे।

ना जानता का जानकारी हो जाता है लामिछाने ने 2018 में अमेरिका नागरिकता का परित्याग कर दिया लामिछाने ने नवंबर, 2022 के अंत तक चुनाव के समय 1994 में प्रथम नेपाली नागरिकता के जो कागज निर्वाचन आयोग को दिये थे, वह कानूनी रूप से अवैध ही थे। यानी फ़ाइड किया था। सही से छानबीन होते तो इस मामले में नेपाल निर्वाचन आयोग भी फ़ंसेगा।

एक सच यह भी है कि रवि लामिछाने को गृह मंत्रालय देखने की प्रचंड सहज नहीं थे। वित्त मंत्रालय एमाले के हिस्से, कोई दमदार मंत्रालय नहीं प्रचंड की पार्टी के पास। प्रचंड दोबारा से गृहमंत्रालय 19 सांसद वाली गणराज्य सरकार पार्टी के तेजा वाली

कुछ इस्तग अपराशन भा किय था। टीवी टॉक शो में रवि लामिछाने की मसीहाई छवि ऐसी बनी कि नेपाल के आम आदमी को लगा कि यह बाकी शब्दियतों से अलग हैं, देश और समाज को बदल देगा। लामिछाने ने 16 जन. 2022 को बाला राष्ट्रीय स्वतंत्र पाटा के नता बवांयों दें भला? 10 जनवरी, 2022 को 275 सदस्यीय प्रतिनिधि सभा जो विश्वासमत हुआ था, उसमें प्रच को 268 वोट मिले थे। विश्वासम जीतने के बास्ते ज़रूरत थी 138 मंकी। 268 में 19 कम हो भी जाते व

